इकाई 11 भारत छोड़ो आन्दोलन*

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 1939 से 1941 के बीच

11.2.1 युद्व के प्रति दृष्टिकोण

11.2.2 व्यक्तिगत सत्याग्रह

11.3 भारत छोड़ो आंदोलन की ओर

11.3.1 क्रिप्स के प्रस्ताव

11.3.2 भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि

11.4 आंदोलन

11.4.1 आंदोलन का प्रसार

11.4.2 प्रतिक्रियाएँ और प्रवृत्तियाँ

11.4.3 दमन

11.5 सारांश

11.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली परिस्थितियों के बारे में जान सकेंगे;
- इस आंदोलन के प्रति भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोणों को समझ सकेंगे;
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस आंदोलन की प्रतिक्रिया के बारे में जान सकेंगे;
- इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के बारे में जान सकेंगे; और
- इस आंदोलन की विशेषताओं और उसके महत्व के बारे में जान सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप को 1939-1945 के दौरान आजादी की लड़ाई की मुख्य राजनीतिक धाराओं से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। इस इकाई में मुख्यतः भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता के संघर्ष में उसकी भूमिका की ही चर्चा की गयी है।

हम यहाँ उस घटनाक्रम की चर्चा करेंगे जिसने अन्ततः भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करवाया। कांग्रेस इस आंदोलन को चलाने और संगठित करने की योजना तैयार भी नहीं कर पायी थी कि सरकार ने इसे आगे न बढ़ने देने के लिए अपना दमन चक्र शुरू

* यह इकाई ई.एच.आई.-01 की इकाई 34 पर आधारित है।

कर दिया। लेकिन सरकार की सारी गणना गलत साबित हुई क्योंकि लोगों ने, कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अपना काम खुद करने का निर्णय लिया और अंग्रेज सरकार को उन्होंने इस तरह से चुनौती देना शुरू किया जिसकी तुलना एक सीमा तक 1857 के संघर्ष से की जा सकती है। नये नेता स्थानीय स्तरों पर उभर कर आए। उनकी भूमिका गांधीवादी संघर्ष से भिन्न थी। अहिंसा का सिद्धांत इस दौर में निदेशक सिद्धांत नहीं रहा। सरकारी सम्पत्ति पर व्यापक हमले होने लगे। हालांकि सरकार इस आंदोलन को कुचलने में सक्षम थी, परन्तु इसकी तीव्रता ने स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेज भारत पर अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकेंगे। यह सच्चाई सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में गठित आजाद हिंद फौज और उसकी कार्रवाई से भी सामने आ रही थी। भारतीय, अंग्रेज सरकार का सशस्त्र विरोध करने में केवल सक्षम ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऐसा किया भी, और आजाद हिंद सरकार का गठन भी किया।

11.2 1939 से 1941 के बीच

आपको 1939 से 1941 के बीच की अवधि में हुई घटनाओं के क्रमिक विकास और उन परिस्थितियों के बारे में जानने में रुचि होगी जो अन्ततः भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बनीं।

11.2.1 युद्ध के प्रति दृष्टिकोण

विश्वयुद्ध के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण आमतौर पर निम्न श्रेणियों में दर्शाया जा सकता है।

i) चूँकि ब्रिटेन संकट में था भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यह निम्न तरह से किया जा सकता था :

- युद्ध के लिए भारतीय संसाधनों को जुटाने के ब्रिटिश प्रयासों का विरोध करके।
- अंग्रेजों के विरुद्ध मजबूत आंदोलन खड़ा करके । इस विचार के प्रतिपादकों की मुख्य चिंता भारत की आजादी प्राप्त करने से थी, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं था।

ii) भारत को ब्रिटेन की समस्याओं से लाभ नहीं उठाना चाहिए। उसे ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में बिना शर्त सहयोग करना चाहिए। जो इस विचार के समर्थक थे, वे सोचते थे कि युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन अपने प्रति भारत की सेवाओं को देखते हुए उनके प्रति नरम रुख अपनाएगा और उसे समुचित रूप से पुरस्कृत करेगा।

iii) बहुत से भारतीय ऐसे थे, जो फासीवाद (फासिज्म) को मानवजाति के लिए बड़ा खतरा मानते थे और युद्ध में ब्रिटेन की मदद करना चाहते थे। लेकिन यह मदद सशर्त थी। ये शर्त थी, भविष्य में भारत की स्वतंत्रता और उस समय के लिए भारतीयों की एक अंतरिम सरकार।

vi) भारतीयों के कुछ वर्ग ऐसे भी थे, जिनका दृष्टिकोण युद्ध की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, बदलता रहा। और ऐसे वर्ग भी थे जिन्होंने तटस्थ रवैया अपनाया।

इस परिस्थिति में कांग्रेस ने क्या किया? व्यवहारिक रूप से पूर्ववर्णित सभी दृष्टिकोण कांग्रेस के भीतर ही मौजूद थे और इन सब के होते एक निश्चित कार्यनीति अपनाना जटिल काम था। इस हालत में कांग्रेस ने युद्ध में ब्रिटेन का पूरा सहयोग देने का प्रस्ताव रखा बशर्ते केन्द्र में एक उत्तरदायी किस्म की सरकार तुरंत गठित कर दी जाए। जहाँ

तक भविष्य का सवाल था कांग्रेस ने एक संविधान सभा के गठन की माँग की जो स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार कर सके। इस तरह यह स्पष्ट है कि जो वर्ग इस समय अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के पक्ष में था, उसे गांधीवादी नेतृत्व ने महत्व नहीं दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों से सवाल किया, ''क्या ग्रेट ब्रिटेन अनिच्छुक भारत को युद्ध में घसीटना चाहेगा या सच्चे लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने इच्छुक साथी का सहयोग पसंद करेगा?'' गांधी जी ने कहा, "कांग्रेस के समर्थन का मतलब होगा कि उससे इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का मनोबल बढ़ जाएगा।"

हालांकि गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सशर्त सहयोग का सर्मथन किया, मगर वे स्वयं इसके पक्ष में नहीं थे जैसा कि उन्होंने बाद में कहा, ''मुझे अफसोस था कि अपने इस विचार में कि ब्रिटिश को जो भी सहयोग दिया जाय वह बिना शर्त दिया जाना चाहिए, मैं अकेला पड़ गया था।'' गांधी जी अपनी निजी हैसियत से, प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति अपने रुख को बार-बार सामने ला रहे थे यानि वे सहयोग की बात दोहरा रहे थे। परंतु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं और अब निजी विचारों से ऊपर उठने का समय था। गांधी जी ने महसूस किया कि उनकी चुप्पी का दूरगामी अर्थ भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए ही हानिकर सिद्ध हो सकता था। अतः उन्होंने कहाः

''अगर अंग्रेज सभी की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके प्रतिनिधियों को स्पष्ट शब्दों में यह बात कहनी चाहिए कि युद्ध के लक्ष्य में भारत की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से शामिल है। इस स्वतंत्रता का मसौदा केवल भारतियों द्वारा, और सिर्फ उन्ही के द्वारा ही तय किया जा सकता है।''

सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? दरअसल अंग्रेज न तो तत्काल कोई छूट देने की स्थिति में थे और न भविष्य के लिए कोई वादा करने की स्थिति में – वे केवल डॉमिनियन स्टेट्स देने की सरसरी बातचीत कर रहे थे। अंग्रेज सरकार के विरोध को रोकने और युद्ध की कार्यवाई में भारतीय संसाधनों के दोहन के लिए भारत रक्षा कानून (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स) लागू कर दिए गए।

11.2.2 व्यक्तिगत सत्याग्रह

नागरिक अवज्ञा शुरू करने के मामले में कांग्रेस के दो मत थे। गांधी जी महसूस करते थे कि वातावरण नागरिक अवज्ञा के अनुकूल नहीं था क्योंकि कांग्रेस के अंदर मतभेद और अनुशासनहींनता की स्थिति बनी हुई थी। जो लोग नागरिक अवज्ञा की वकालत कर रहे थे, वे गांधी जी को यह विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि एक बार आंदोलन शुरू हो जाए तो मतभेद समाप्त हो जाएँगे और सभी इसकी सफलता के लिए काम करने लगेंगे। परन्तु गांधी जी इस तर्क से सहमत नहीं थे। कांग्रेसी समाजवादी और अखिल भारतीय किसान सभा तुरंत आंदोलन शुरू करने के पक्ष में थे। एन. जी. रंगा ने तो यह सुझाव भी दिया कि किसान सभा को कांग्रेस से संबंध तोड़ लेने चाहिए और एक स्वतंत्र आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन किसी तरह पी. सुंदरैया ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और इसी तरह के वातावरण में मार्च 1940 में मौलाना आजाद के नेतृत्व में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ। मौलाना ने कहा :

> ''भारत नाजीवाद और फासीवाद की सम्भावनाओं को सहन नहीं कर सकता, परंतु वह इससे भी ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उकता गया है''।

रामगढ़ कांग्रेस ने लोगों का आह्वान किया कि वे गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाले सत्याग्रह में भाग लेने के लिए स्वयं को तैयार करें। लेकिन समाजवादी, साम्यवादी, किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित लोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। उन्होने रामगढ़ में एक समझौता-विरोधी सम्मेलन बुलाया। और सुभाषचंद्र बोस ने लोगों

से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवाद से समझौते का विरोध करें और कार्यवाई के लिए तैयार रहें। अगस्त 1940 में वाइसरॉय ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें निम्न बातें शामिल थीं :

- गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो।
- युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना।

इस प्रस्ताव में उसने मुस्लिम लीग और अन्य अल्पसंख्यकों से वादा किया कि अंग्रेज सरकार भारत में ऐसे संविधान या सरकार पर कभी भी सहमत नहीं होगी जिसे उनका समर्थन प्राप्त न हो। (यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि 1940 के अपने लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग रख चुकी थी)।

कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि :

1) इसमें राष्ट्रीय सरकार के लिए कोई सुझाव नहीं था,

2) इसमें मुस्लिम लीग जैसी कांग्रेस विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया गया था।

सरकार योजनाबद्ध तरीकों से निवारक नजरबंदी के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही थी विशेष रूप से उन्हें जो समाजवादी या वामपंथी रुझान वाले थे। सभी स्थानीय नेताओं पर निगरानी रखी जा रही थी। जब कि बहुत से मजदूर नेताओं और युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

जब गांधी जी को पक्का भरोसा हो गया कि अंग्रेज भारत में अपनी नीति में कोई सुधार नहीं करेंगे (गांधी जी ने सितम्बर 1940 में शिमला में वाइसराय के साथ लम्बी-लम्बी बैठकें कीं) तो उन्होने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। आंदोलन को व्यक्तिगत भागीदारी तक सीमित रखने का कारण यह था कि गांधी जी और कांग्रेस दोनों में से कोई भी यह नहीं चाहता था कि युद्ध के प्रयासों में बाधा डाली जाए, जब कि जन आंदोलन में ऐसा होना संभव नहीं था। यहाँ तक कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का लक्ष्य भी सीमित था, यानी इस ब्रिटिश दावे को झुठलाना कि भारत पूरे मन से युद्ध की कार्यवाई में साथ दे रहा है।

17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने वर्धा के निकट एक गाँव पवनार में युद्ध विरोधी भाषण देकर इस सत्याग्रह का उद्घाटन किया। इस काम के लिए गांधी जी ने भावे को निजी तौर पर चुना था। उनके दो अन्य नामजद लोग वल्लभभाई और नेहरू सत्याग्रह शुरू करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। नवम्बर 1940 और फरवरी 1941 के मध्य बहुत से प्रमुख कांग्रेसजन जेल गए, लेकिन भागीदारी की सीमित प्रकृति और गांधी जी द्वारा कांग्रेसियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यह आंदोलन अधिक कुछ हासिल नहीं कर सका। कुछ मामलों में कांग्रेसी भी बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे। उदाहरण के लिए, बिहार में सत्याग्रह के लिए चुने गए बहुत से कांग्रेसी अपने उन पदों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जो वे नगरपालिकाओं में हासिल किए हुए थे। उन्होंने या तो गिरफ्तारी देने से स्पष्ट इंकार कर दिया या फिर गिरफ्तारी देने के मामले में बहुत धीमापन दिखाया।

दिसम्बर 1941 में कांग्रेस कार्यसमिति ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। इस समय तक युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया था। ब्रिटेन की हार पर हार हो रही थी और जापानी फौजें दक्षिण-पूर्व एशिया को रौंद चुकी थीं। सोवियत संघ पर नाजियों का हमला हो चुका था और ब्रिटेन पर सोवियत संघ, अमरीका तथा चीन यह दबाव डाल रहे थे कि वह अपनी भारतीय नीति पर पुनर्विचार करें। सरकार ने अनेक राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। जापान के हाथों रंगून के पतन के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रिप्स कमीशन भारत भेजने का निर्णय किया।

बोध प्रश्न 1

1) युद्ध के प्रति भारतीयों के दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही (✓) या गलत (✗) है?

i) गांधी जी को अफसोस था कि एकमात्र वे ही ऐसे हैं जो युद्ध के दौरान ब्रिटिश को बिना शर्त सहयोग देना चाहते थे।

ii) गांधी जी युद्ध प्रयासों के लिए ब्रिटेन को सशर्त समर्थन देने के लिए राजी हो गए।

iii) भारत रक्षा कानून कांग्रेस के हितों की रक्षा के लिए थे।

iv) कांग्रेस फासीवाद और नाजीवाद की विरोधी थी।

v) कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

vi) व्यक्तिगत सत्याग्रह 1947 तक जारी रहा।

11.3 भारत छोड़ो आंदोलन की ओर

युद्ध की प्रतिकूल परिस्थितिओं और अंतर्राष्ट्रीय दबावों ने अंग्रेजों को भारत के साथ एक सौहार्दपूर्ण समझौता करने और युद्ध में उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए विवश कर दिया। सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स कुछ प्रस्तावों के साथ भारत आए और उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की।

11.3.1 क्रिप्स के प्रस्ताव

क्रिप्स के कुछ प्रस्ताव जो घोषणा-पत्र के प्रारूप में शामिल थे, इस प्रकार थे :

- युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद भारत को, पृथक होने के अधिकार सहित, डॉमिनियन स्टेट्स दे दिया जाएगा।
- युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। इसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे।
- इस तरह युद्धोपंरात बनाया गया संविधान अंग्रेज सरकार द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा कि कोई भी भारतीय प्रांत यदि वह चाहे तो भारतीय संघ से बाहर रह सकेगा और इस मसले पर ब्रिटेन से सीधी बातचीत कर सकेगा।
- रक्षा और सैनिक कार्यवाइयों का वास्तविक नियंत्रण अंग्रेज सरकार के पास रहेगा।

इस घोषणा-पत्र को तकरीबन सभी भारतीय पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस भविष्य के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। वह पूर्ण अधिकारों सहित उत्तरदायी सरकार और देश की रक्षा पर नियंत्रण भी चाहती थी। गांधी जी ने प्रस्तावों की उपमा ''एक दिवालिया बैंक के नाम काटे गए उत्तर दिनांकित चेक'' से दी । मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाए जाने के संबंध में अंग्रेज द्वारा एक स्पष्ट

घोषणा किए जाने की माँग की, और साथ ही अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के लिए 50 : 50 के आधार पर सीटों की माँग भी रखी। दलित वर्गों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों और एंगलो-इंडियनों ने अपने-अपने समुदायों के लिए रक्षा उपायों की माँगें रखीं। इस तरह क्रिप्स कमीशन भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहा। ब्रिटेन ने यह सारा प्रयोग वास्तव में कोई ठोस काम करने के बजाए दुनिया को यह दिखाने के लिए ज्यादा किया था कि वह भारत की भावनाओं की चिंता करता है।

11.3.2 भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि

कांग्रेस को अपने भावी काम की दिशा जिन स्थितियों के चलते तय करनी पड़ी वे थीं :

- क्रिप्स मिशन की असफलता,
- जापानी सेना का भारत की सीमाओं तक आ पहुँचना,
- बढ़ती हुई कीमतें और खाद्य आपूर्ति की कमी, और
- कांग्रेस के अंदर अलग-अलग मत।

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत पर हमला करने वाली किसी भी विदेशी ताकत के साथ पूर्ण अहिंसक असहयोग करने का आह्वान किया गया (मई, 1942)। राजगोपालाचारी और मद्रास के कुछ अन्य कांग्रेसियों ने एक प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयास किया जिसमें कहा गया था कि अगर मद्रास सरकार उन्हें आमंत्रित करती है तो कांग्रेस को वहाँ मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए। इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया परन्तु इस प्रस्ताव ने यह जाहिर कर दिया कि कुछ ऐसे कांग्रेसी थे, जो सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे। राजगोपालाचारी एक स्वतंत्र रास्ता अपना रहे थे। वे पाकिस्तान की माँग का समर्थन कर चुके थे और कांग्रेस से आग्रह कर रहे थे कि वह युद्ध में सहयोग करें।

मई, 1942 में गांधी जी ने बंबई में कांग्रेसियों की एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्होंने तय कर लिया है कि वे आदेशात्मक स्वर में अंग्रेजों से भारत छोडने के लिए कहेंगे। अगर अंग्रेज नहीं मानेंगे तो वे नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। इस आंदोलन को शुरू करने के बारे में बहुत से कांग्रेसी नेताओं के मन में संकोच था। नेहरू विशेष रूप से दुविधा में थे कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन से संघर्ष करें या फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष में सोवियत संघ और चीन का साथ दें। आखिरकार नेहरू ने आंदोलन शुरू करने के पक्ष में फैसला किया। कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत छोड़ो माँग का मतलब यह नहीं कि ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की फौजें तुरंत ही भारत से चली जाएँ। बल्कि इसका तात्पर्य था कि अंग्रेजों द्वारा भारत की स्वतंत्रता को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाएँ 14 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया जिसकी पुष्टि अगस्त में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में की जानी थी।

8 अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ''भारत छोड़ो प्रस्ताव'' पारित कर दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद , कांग्रेस ने भारत के लोगों से अपील की:

''उन्हें याद रखना चाहिए कि इस आंदोलन का आधार है। एक समय ऐसा आ सकता है कि जब लोगों के लिए निर्देश जारी करना, या निर्देश के लिए जनता तक पहुँचाना संभव न हो और जब कोई कांग्रेस कमेटी काम न कर सके। अगर ऐसा हो तो प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जो इस आंदोलन में भाग ले रहा है, जारी किए गए सामान्य निर्देशों की चौहद्दी में रहकर स्वयं अपने अनुसार, काम करना चाहिए।''

गांधी जी ने अंग्रेजों से यहाँ से चले जाने और ''भारत को भगवान भरोसे छोड़ने'' के लिए कहा। उन्होंने सभी वर्गों को प्रोत्साहित किया कि वे आंदोलन में भाग लें और उन्होंने जोर दे कर कहा ''प्रत्येक भारतीय को जो आजादी चाहता है और इसके लिए प्रयत्न करना चाहता है अपना अगुआ स्वयं बनना चाहिए।'' उनका संदेश था ''करो या मरो''। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया।

11.4 आंदोलन

कांग्रेस ने अंग्रेजों को निकाल बाहर करने का आह्वान तो किया लेकिन इसने पालन के लिए लोगों को कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं दिया। सरकार इस आंदोलन को कुचलने की तैयारियाँ कर रही थी। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। नेताओं की गिरफ्तारी ने लोगों को धक्का पहुँचाया और वे विरोध के लिए सड़कों पर निकल आए। के. जी. मशरूवाला ने जो *हरिजन* के सम्पादक हो गए थे, विरोध की संभावित रूपरेखा के बारे में अपनी निजी राय प्रकाशित की :

''मेरी राय में, कार्यालयों, बैंकों, अन्न भन्डारों की लूटपाट या आगजनी उचित नहीं है। यातायात संचार व्यवस्था अहिसंक तरीके से और जीवन को खतरे में डाले बिना भंग करना उचित है। हड़तालों का आयोजन करना सर्वश्रेष्ठ है.... तार काटना, पटरी उखाड़ना, छोटे पुलों को नष्ट करना आदि को इस प्रकार के संघर्ष में अनुचित नहीं ठहराया जा सकता, बशर्ते कि जीवन की सुरक्षा की अत्यधिक सावधानी बरती जाएँ''

मशरूवाला ने कहा, ''गांधी जी और कांग्रेस ने, अंग्रेज और भारतीय राष्ट्रों के बीच फिर से सद्भाव पैदा होने की सभी उम्मीदें नहीं छोड़ दी हैं, यदि प्रयास राष्ट्रीय इच्छा को प्रगट करने के लिए काफी शक्तिशाली है, तो आत्मसंयम कभी भी हमारे विरुद्ध नहीं जाएगा''

अब हम इस आंदोलन के प्रसार और विभिन्न वर्गो पर इसके प्रभाव की थोड़ी चर्चा करें।

11.4.1 आंदोलन का प्रसार

9 अगस्त को अपनी गिरफ्तारी से पूर्व गांधी जी ने देश के नाम निम्न संदेश दिया थाः

''प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है कि वह हड़ताल तथा अन्य अहिंसक साधनों से गतिरोध पूरा करने के लिए अहिंसा के अंतर्गत अपनी आखिरी हदों तक काम करे। सत्याग्रहियों को जीवन के लिए नहीं बल्कि मृत्यु के लिए बाहर निकलना है। उन्हें मृत्यु का सामना करना है, उसे गले लगाना है । तब प्रत्येक व्यक्ति करेंगे या मरेंगे की भावना के साथ बलिदान के लिए निकलेगा तभी देश जीवित रहेगा।''

लेकिन यह संदेश देने के साथ गांधी जी ने एक बार फिर अहिंसा पर बल दियाः

''स्वतंत्रता के प्रत्येक अहिंसक सेनानी को ''करेंगे या मरेंगे'' का नारा एक कागज या कपड़े के टुकड़े पर लिखना चाहिए और उसे अपने कपड़ों पर चिपकाना चाहिए ताकि सत्याग्रह के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे उन दूसरे तत्वों से अलग किया जा सके जो अहिंसा का समर्थन नहीं करते।''

गांधी जी और उनके साथ अन्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी पर देश के विभिन्न भागों में अभूतपूर्व जन प्रतिक्रिया हुई। शहरों और कस्बों में हड़तालों जुलूस और प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि आह्वान कांग्रेसी नेतृत्व का था, परन्तु वास्तव में आंदोलन जनता ने शुरू किया। चूंकि राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर के स्तर के सभी मान्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, इसलिए इनकी जगह भरने के लिए उनके क्षेत्रों में स्थानीय स्तरों पर युवा और उग्र, विशेषरूप से समाजवादी रुझान वाले, छात्र नेता उभर कर आए।

प्रारंभिक चरणों में आंदोलन अहिंसा की सीमाओं में रहा। सरकार की दमनकारी नीति ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। अहिंसक संघर्ष का गांधी जी का संदेश पृष्ठभूमि में चला गया और लोगों ने संघर्ष के अपने-अपने तरीके ढूँढ़ निकाले। इनमें ये कदम शामिल थेः

- सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और डाकघरों पर हमले,
- रेलवे स्टेशनों पर हमले, और रेल की पटरियों को उखाड़ना,
- टेलीग्राफ, टेलीफोन और बिजली के तारों को काटना,
- पुलों को नष्ट करके सड़क यातायात भंग करना, और
- मजदूरों की हड़ताल आदि।

इनमें से अधिकांश कार्यवाइयाँ सेना और पुलिस की गतिविधि को रोकने के लिए थीं, जिनका इस्तेमाल सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए कर रही थी। कई क्षेत्रों में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया और यहाँ स्थानीय जनता ने स्वराज कायम कर दिया। कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं।

- महाराष्ट्र में, सतारा में एक समानान्तर सरकार स्थापित कर दी गई जो लम्बे समय तक चलती रही।
- बंगाल में, तामलुक जातीय सरकार मिदनापुर जिले में काफी समय तक काम करती रही। इस राष्ट्रीय सरकार के पास कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि विभागों के साथ-साथ अपनी डाक व्यवस्था तथा विवाचन (Arbitration) अदालतें भी थीं।
- उड़ीसा में तलचर (Talacher) में लोगों ने स्वराज स्थापित किया।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों में (आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर इत्यादि) लोगों ने पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया और सरकारी सत्ता को उखाड़ फेंका।

प्रारंभ में यह आंदोलन शहरी इलाकों में ही प्रभावी था, परंतु शीघ्र ही इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गया जहाँ विद्रोह का झंडा लम्बे समय तक ऊँचा उठा रहा। बम्बई, आंध्र, यूपी, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, असम, बंगाल कर्नाटक, आदि में आंदोलन को जनता का व्यापक समर्थन मिला। लेकिन पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमाप्रांत में आंदोलन का प्रभाव कम था।

11.4.2 प्रतिक्रियाएँ और प्रवृत्तियाँ

''भारत छोड़ो'' और ''करो या मरो'' उस समय के प्रमुख नारे थे, परंतु आंदोलन के प्रति जनता ने कई रूपों में अपनी सक्रियता दिखाई। श्रमिक वर्ग ने कई औद्योगिक केन्द्रों में हड़तालें कीं। इनमें से कुछ प्रमुख केन्द्र थे बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर और पूना। दिल्ली में 9 अगस्त की हड़ताल मजदूरों के सड़क पर निकल आने का परिणाम थी। लेकिन अहमदाबाद को छोड़कर, जहाँ हड़ताल तीन महीने चली, अन्य जगहों पर हड़ताल ज्यादा दिन नहीं चली।

बिहार में व्यापक जन कार्यवाइयों के परिणामस्वरूप पटना शेष इलाके से कट गया, और उत्तरी क्षेत्र में बेगूसराय के उपमंडल (सब-डिवीजन) अधिकारी ने रिपोर्ट दीः

''स्कूली विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू किया, कांग्रेस के सभी वर्गो के कार्यकर्ता उनके साथ शामिल हो गए। कांग्रेस के नरम वर्ग ने आंदोलन को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होन ग्रामीण जनता को आंदोलन में शामिल किया तो यह एक

आर्थिक प्रश्न बन गया, विशाल सम्पत्तियों खासकर रेलवे स्टेशनों पर पड़े अनाज ने उन्हें आकर्षित किया ... गरीब मजदूरों ने लूट में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। दूरस्थ स्टेशनों पर व्यापारी वर्ग कांग्रेस की दया पर निर्भर था। ... नरम वर्ग ने यह सब पसंद नहीं किया, परंतु उस समय उनका कोई नियंत्रण नहीं था।''

इससे आंदोलन में ग्रामीण जनता की भागीदारी और नेताओं (नरम वर्ग के रूप में वर्णित) की आंदोलन को निर्देशित करने की मजबूरियों का पता चलता है। इसी तरह के हालात पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थे। आजमगढ़ जिले के मधुबन थाने में जो कुछ हुआ, उसके आर. एच. निबलेट द्वारा रखे गए लेखे-जोखे से इस क्षेत्र में जनता के विद्रोह की भयानकता का आभास होता है। निबलेट ने उल्लेख किया है कि किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से पुलिस स्टेशन पर तीन ओर से हमला किया गया। एक ओर से चलने वाले लोग जल्दी पहुँच गए तो उन्होने दूसरी ओर से आने वाले लोगों की एक निश्चित फासले पर खड़े होकर प्रतीक्षा की । पुलिस ने हमले को रोकने के लिए 119 चक्र गोलियाँ चलायीं। हमला करीब दो घंटे तक चला। उड़ीसा में तलचर (Talacher) कस्बे की ओर बढ़ते हुए किसान गुरिल्लों को रोकने के लिए हवाई जहाजों का प्रयोग किया गया। महाराष्ट्र में सतारा क्षेत्र में लम्बी मुठभेड़ें चलीं।

व्यापक जन कार्रवाई के अलावा आंदोलन में एक और प्रवृत्ति उभर कर आयी। प्रवृत्ति थी भूमिगत, क्रांतिकारी कार्रवाई की। 9 नवम्बर 1942 को जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्रा हजारीबाग जेल से भाग निकले। उन्होने नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों से भूमिगत आंदोलन का संचालन किया।

इसी प्रकार बंबई में, अरूणा आसिफ अली जैसी नेता के नेतृत्व में समाजवादी नेताओं ने अपनी भूमिगत गतिविधियाँ जारी रखीं। भूमिगत आंदोलन की सबसे साहसपूर्ण कार्रवाई कांग्रेस रेडियो की स्थापना थी, जिसकी उद्घोषिका ऊषा मेहता थी। यह रेडियो लम्बे समय तक सक्रिय रहा। सुभाषचंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो पर बोलते हुए (31 अगस्त, 1942) इस आंदोलन को ''अहिंसक गुरिल्ला युद्व'' कहा। उन्होने सुझाव दिया कि:

''इस अहिंसक गुरिल्ला अभियान का लक्ष्य दुहरा होना चाहिए। पहला भारत में युद्व उत्पादनों को नष्ट करना और दूसरा देश में अंग्रेज प्रशासन को ठप्प करना। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी वर्गों को इस संघर्ष में भाग लेना चाहिए।''

आंदोलन में छात्रों ने व्यापक रूप से भाग लिया। वे देहात में फैल गए और वहाँ ग्रामीणों को दिशा-निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन को व्यापारी वर्ग का ज्यादा समर्थन नहीं मिला। वास्तव में अधिकांश पूँजीपतियों और व्यापारियों ने युद्व के दौरान भारी मुनाफा कमाया था। कुछ मामलों में पूँजीपतियों ने सरकार से (फिक्की-फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से) गांधी जी और अन्य नेताओं को रिहा करने का आग्रह किया। लेकिन उनका तर्क था कि अकेले गांधी जी ही सरकारी सम्पत्तियों पर हो रहे हमलों को रोक सकते हैं। वे चिंतित थे कि इस तरह के हमले अगर जारी रहे तो वे निजी संपत्ति पर हमले के रूप में बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग ने स्वयं को इस आंदोलन से दूर रखा। इस दौरान साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं के समाचार भी नहीं मिलें। हिंदू महासभा ने आंदोलन की आलोचना की । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी ''जन युद्व की नीति'' के कारण आंदोलन का समर्थन नहीं किया। राजा और जमींदार युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रहे थे। आंदोलन के साथ उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। राजगोपालाचारी जैसे कुछ कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया और जिन्होंने युद्व प्रयासों का समर्थन किया।

इस सबके बावजूद आंदोलन की तीव्रता निम्न आँकड़ों से मापी जा सकती है :

- यू. पी. में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 104 रेलवे स्टेशनों पर हमला किया गया और क्षति पहुँचाई गयी। लगभग 100 घटनाएँ रेलपटरियों की तोड़-फोड़ की हुईं। टेलीफोन और टेलीग्राफ तार काटने के 425 मामले हुए। डाकघरों को क्षति पहुँचाने की 119 घटनाएँ हुई।
- मिदनापुर में 43 सरकारी इमारतों में आग लगाई गई।
- बिहार में 72 पुलिस थानों पर हमले हुए, 332 रेलवे स्टेशनों, 945 डाकघरों को क्षति पहुँचाई गयी।
- देशभर में 664 बम विस्फोट हुए।

इस व्यापक जन लहर की सरकार पर क्या प्रतिक्रिया हुई? इस सवाल की चर्चा हम आगामी भाग में करेंगे।

11.4.3 दमन

व्यापक जन आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। गिरफ्तारियाँ, नजरबंदियाँ, पुलिस द्वारा गोली चलाना, कांग्रेस कार्यालयों को आग लगाना, आदि। वे तरीके थे जो सरकार ने अपनाए।

- 1942 के अंत तक अकेले यू. पी. में 16,089 लोग गिरफ्तार किए गए। सारे भारत में 1943 के अंत तक गिरफ्तारियों का सरकारी आँकड़ा 91,836 था।
- सितम्बर 1942 तक पुलिस गोली चलने में मारे गए लोगों की संख्या 658 थी, और 1943 तक यह संख्या 1060 हो गई थी। लेकिन ये सरकारी आँकड़े थे। वस्तुतः इससे कहीं अधिक लोग मरे थे और बहुत से घायल हुए थे।
- अकेले मिदनापुर में सरकारी बलों ने 31 कांग्रेस शिविरों और 164 निजी घरों को आग लगायी थी। बलात्कार के 74 मामले हुए। इनमें से 46 पुलिस द्वारा एक ही दिन में एक ही गाँव में 9 जनवरी 1943 को किए गए थे।
- सरकार ने 5 स्थानों पर लोगों पर गोली चलाने के लिए हवाई जहाजों के प्रयोग की बात स्वीकार की। ये स्थान थे पटना के निकट गिरिक (Giriak) भागलपुर जिला, नाडिया जिले में रामाघाट, मुंगेर जिला, और तलचर शहर के निकट।
- लाठी चार्ज, कोड़े मारने, बंदी बनाने की अनगिनत घटनाएँ हुईं।
- आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया। उदाहरण के लिए, यूपी में इस तरह के जुर्माने की कुल धनराशि 28,32,000 रुपए थी, और फरवरी 1943 तक 25,00,000 रुपए वसूल कर लिए गए थे। इसी प्रकार उत्तरी बिहार में फरवरी 1943 तक रु. 34,15,529 का जुर्माना किया जा चुका था, जिसमें से रु. 28,35,025 वसूल कर लिए गए थे।

इस प्रकार के दमनकारी तरीकों से ही अंग्रेज खुद को फिर से जमाने में सफल हो गए। युद्व की स्थिति ने दो तरह से उनकी मदद की:

i) उनके हाथ में विशाल शैन्य शक्ति थी, जो भारत में जापानी हमले के मुकाबले के लिए रखी गई थी, परन्तु इस शक्ति का उपयोग आंदोलन को कुचलने में किया गया।

ii) युद्वकालीन सेंसर स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने आंदोलन को निर्मम ढंग से दबा दिया। उन्हें अपने इन दमनकारी तरीकों के लिए न तो किसी आंतरिक (घरेलू) आलोचना की चिंता करनी थी, और न विश्व जनमत की। मित्र राष्ट्र, धुरी

राष्ट्रों के साथ युद्व में उलझे थे, उनके पास यह चिंता करने का समय नहीं था कि अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे।

भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया। परन्तु इसने अंग्रेजी राज्य से छुटकारा पाने के लिए जनता के दृढ़ इरादे को बखूबी जाहिर कर दिया। कांग्रेसी नेतृत्व ने अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए लोगों की आलोचना नहीं की लेकिन साथ ही लोगों के किसी भी हिंसक कृत्य के लिए जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया।

बोध प्रश्न 2

1) निम्न में से कौन से कथन सही (✓) या गलत (✗) हैं।

   i) गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में जनता के सीमित वर्गों की ही भागीदारी चाहते थे।

   ii) भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व उग्र युवकों और समाजवादियों के हाथों में चला गया।

   iii) भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोई समानान्तर सरकार स्थापित नहीं हुई।

   iv) कांग्रेस के नरम वर्ग ने आंदोलन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा।

   v) आंदोलन के दौरान कोई भूमिगत कार्रवाई नहीं चली।

   vi) भारत छोड़ो आंदोलन में पूँजीपतियों और व्यापारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

2) भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों द्वारा अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए।

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

3) व्यापक जन आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए।

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

11.5 सारांश

युद्व के प्रति भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों के विभिन्न दृष्टिकोण थे, और ये सब कांग्रेस में प्रतिबिम्बित होते थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, सहभागिता की सीमित प्रवृत्तित के कारण, व्यापक रूप से प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ।

भारत को युद्ध में घसीट लिए जाने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, मगर इस आंदोलन के निर्णय तक पहुँचने में तीन साल का समय लगा। आंदोलन शुरू करने की घोषणा के साथ ही अंग्रेजों ने निष्ठुर दमन की नीति अपनायी। रातों रात कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और कांग्रेस को एक निश्चित कार्य दिशा तय करने का समय तक नहीं मिल सका। फिर भी आंदोलन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा। लोगों ने अपने-अपने स्तर पर कार्य दिशाएँ तय कर लीं। आंदोलन को नेतृत्व देने में युवक और समाजवादी अग्रिम मोर्चे पर रहे। अपने प्रारम्भिक चरण में शहर के लोग ही आंदोलन में सक्रिय रहे, मगर शीघ्र ही आंदोलन देहात में भी फैल गया। कई क्षेत्रों में अंग्रेज सरकार उखाड़ दी गई और समानान्तर सरकारों की स्थापना कर दी गई। इस संघर्ष में लोगों द्वारा अपनाए गए तरीके गांधी जी की अहिंसा की सीमाओं से बाहर निकल गए और कांग्रेस का उदार वर्ग उन पर नियंत्रण नहीं रख सका।

अंग्रेज आंदोलन को कुचलने में सफल हो गए, परन्तु भूमिगत कार्रवाइयाँ लम्बे समय तक चलती रहीं। इस आंदोलन ने अंग्रेजों के सामने स्पष्ट कर दिया कि लम्बे समय तक भारत पर कब्जा किए रहना उनके लिए संभव नहीं होगा, और आजाद हिंद फौज द्वारा चलाए गए साहसिक संघर्ष ने इसी बात को फिर से पुष्ट किया।

11.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में उपभाग 11.2.1 में उल्लिखित चार विचारों का समावेश होना चाहिए।

2) i) ✓ ii) ✓ iii) ✗ iv) ✓ v) ✗ vi) ✗

बोध प्रश्न 2

1) i) ✗ ii) ✓ iii) ✗ iv) ✓ v) ✗ vi) ✗

2) अपने उत्तर को उपभाग 11.4.1 और 11.4.2 के पाठों पर आधारित कीजिए। इसमें पुलिस थानों पर हमले, समानान्तर सरकारों का गठन जैसी जनता की कार्यवाइयों को शामिल किया जाना चाहिए।

3) ये थे, जुर्माना करना, लोगों पर गोली चलाना, गिरफ्तारियाँ इत्यादि। देखिए उपभाग 11.4.3।